मराठवाड़ा विकास समिति द्वारा नई रेलगाड़ियों की मांग

2204. **डा० बापू कालदाते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मराठवाड़ा विकास समिति ने सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार मनमाड-औरंगाबाद रेल लाइन पर कब तक नई रेलगाड़ियां चलाने का विचार रखती है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ग) समिति की मांग पर 15-6-92 से औरंगाबाद और मनमाड के बीच एक जोड़ी पैसेंजर गाड़ी चला दी गई है।

विवरण

समिति की मांगों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1. मराठवाड़ा रेल परियोजनाओं के लिए "कोंकण रेलवे प्राधिकरण" की तरह "मराठवाड़ा रेलवे प्राधिकरण" का गठन किया जाए ।

2. औरंगाबाद-आदिलाबाद लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए 600 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जाएं ।

3. बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन का कार्य दोनों छोर अर्थात औरंगाबाद और आदिलाबाद से एक साथ शुरू किया जाए।

4. परली-बीड-अहमदनगर को जोड़ने वाली एक नई रेल लाइन बिछायी जाए।

5. लातूर-कुर्डुवाडी-मिरज लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन ।

6. नांदेड़ रेल मंडल के लिए कार्य की गति तेज की जाए ।

7. औरंगाबाद और बंबई के बीच, एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई जाएं जो एलोरा और अजन्ता एक्सप्रेस गाड़ियों से कनेक्शन सुनिश्चित करें, वापसी यात्रा के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए ।

8. आदिलाबाद और औरंगाबाद के बीच एक नई एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जाए।

9. औरंगाबाद और मनमाड के बीच एक शटल सेवा शुरु की जाए ।

10. मीनाक्षी एक्सप्रेस का चालन क्षेत्र नई दिल्ली तक बढ़ाया जाए ।

11. मराठवाड़ा में पड़ने वाले दक्षिण-मध्य रेलवे के भाग को मध्य रेलवे से संबद्ध कर दिया जाए ।

12. नांदेड़ में हिंगोली गेट निचले पुल का निर्माण।

खतरों के प्रति सुरक्षा के लिये धनराशी

2205 **श्री ईश दत्त यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश को रेलवे सुरक्षा कार्य निधि (रेलवेज फंड फॉर सिक्यूरिटी अगस्ट हजार्ड्स) से कितनी धनराशि दी गई थी ;

(ख) अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) इस धनराशि से कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की प्रतिपूर्ति के लिए इस